मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंजूर, यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में होगा 15189 करोड़ का निवेश

हरदोई समेत नौ जिलों में लगेंगी 12 औद्योगिक इकाइयां

फैसला 1

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में मिर्जापुर व हरदोई समेत नौ जिलों में 12 औद्योगिक इकाईयां लगाई जाएंगी। विभिन्न क्षेत्रों में 15189 करोड़ रुपये का निवेश होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के आधार पर उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के आधार पर यह मंजूरी दी गई।

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि अर्थस्टार वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को मिर्जापुर में 549.26 करोड़ की लागत से आयरन एवं स्टील प्लांट लगाएगी। अपोलो कोटेड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सिकंदराबाद बुलंदशहर में 350 करोड़ से कोल्ड रोलिंग मिल, हल्दीराम स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रा.लिमिटेड हरदोई में 349.27 करोड़ की लागत से स्नैक्स प्लांट लगाएगी। श्री भवानी पेपर मिल्स लिमिटेड रायबरेली में 305 करोड़ से पेपर मिल, ड्रीमटेक इलेक्ट्रानिक्स इंडिया प्राइवेट लि.ग्रेनो में 414.88 करोड़ से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लांट, एसीसी लिमिटेड सलाई बनवा ग्रीनफील्ड ग्राइंडिंग यूनिट सोनभद्र में 803 करोड़ से सीमेंट फैक्ट्री, एनएसएल रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड मेरठ में 4,499.51 करोड़ से सोलर इंटिग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाएगी।

नोएडा योजना में जमीन देने वालों को सहूलियत

लखनऊ। राज्य सरकार ने नोएडा योजना में एक्सवेंज यानी बदले के आधार पर भूमि पाने वालों को राहत देते हुए नक्शा पास कराने की सुविधा दे दी है। अभी तक ऐसे भूखंड स्वामियों को नक्शा पास कराने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

काशी नरेश विवि में अगले वर्ष से प्रवेश

लखनऊ। यूपी में दो नए राज्य विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी राज्य सरकार की ओर से दिए जाने के बाद अब विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में इन दोनों के विधेयक पेश किए जाएंगे। सोमवार को कैबिनेट ने इन दोनों विश्वविद्यालयों का विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। भदोही के काशी नरेश विवि में अगले सत्र से ही प्रवेश शुरू होंगे। भदोही के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को उच्चीकृत कर राज्य विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। भदोही व आसपास के जिलों के छात्रों को उच्च शिक्षा व शोध के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। शैक्षिक सत्र 2026-27 से ही इस विश्वविद्यालय में प्रवेश शुरू किए जाएंगे।

लखनऊ समेत तीन जिलों में 8 कामकाजी महिला हॉस्टल बनाने को 1रु. प्रतिवर्ष लीजरेंट पर जमीन

लखनऊ। यूपी में लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद में महिला कल्याण विभाग आठ कामकाजी महिला हॉस्टल बनाने जा रहा है। जिसके लिए महिला कल्याण विभाग को इन जिलों के विकास प्राधिकरणों की ओर से एक रुपये प्रति वर्ष लीजरेंट पर मुफ्त जमीन दी जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है। फिलहाल यह हॉस्टल बनने से कामकाजी महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। तीन जिलों मे आठहॉस्टल बनाए जाएंगे। हॉस्टल बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था संबंधित विकास प्राधिकरणों से एक रुपये प्रति वर्ष लीजरेंट पर मुफ्त जमीन लेकर की जा रही है।

उपनियंत्रक पदों पर विभागीय अधिकारी तैनात होंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अब सभी जिलों में नागरिक सुरक्षा के उपनियंत्रक पदों पर विभागीय अफसरों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट में सोमवार को उप्र नागरिक सुरक्षा उप नियत्रक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2025 के तहत इस प्रस्ताव को लागू करने की मंजूरी दे दी गई। अभी तक यह व्यवस्था सिर्फ 26 जिलों में प्रभावी थी। इसे सभी जिलों में लागू करने की मांग काफी समय से हो रही थी।

गोरखपुर में वानिकी व औद्यानिकी विवि

लखनऊ। गोरखपुर को जल्द ही प्रदेश का पहला वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने संबंधी प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली इस परियोजना को केंद्र पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है। इस विवि की स्थापना कैम्पियरगंज रेंज के भारी वैसी वन ब्लॉक में 50 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि पर बनेगा। अनुमानित लागत 621.26 करोड़ रुपये आंकी गई है।

आजमगढ़ में नई आवासीय योजना के लिए 100 करोड़

लखनऊ। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को नई आवासीय योजना लाने के लिए 100 करोड़ रुपये दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के भत्ते बढ़े

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने हुए कैबिनेट ने हाईकोर्ट इलाहाबाद/लखनऊ के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश व सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनकी पत्नी को घरेलू सेवक व टेलीफोन भत्ते को बढ़ाने के प्रस्ताव को पास कर दिया है।

अन्य फैसले

- भदोही में सीतामढ़ी-धनतुलसी-डेगरपुर घाट पर पीपा पुल के स्थान पर स्थाई पुल बनेगा
- प्रयागराज में गंगा नदी पर सलोरी हेतापट्टी झूसी मार्ग को जोड़ने के लिए फुटपाथ सहित चार लेन का सेतु, पहुंच मार्ग बनेगा।
- आरईसी व पीएफसी द्वारा स्वीकृत ऋण सीमा बढ़ाकर 12,000 करोड़ की गई।
- राज्य कर्मचारियों के टीए-डीए आदि वेतीय प्रावधानों में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की कैग रिपोर्ट विधानमंडल में रखने से पहले राज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी।

धान खरीद के लिए 1.67 लाख बोरी खरीद को मंजूरी

लखनऊ। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीद के लिए 1.67 लाख बोरियों की खरीद को मंजूरी दी। केन्द्र की ओर से आवंटित इन बोरों की खरीद पर 200 करोड़ रुपये से अधिक राशि का आवंटित किया जाना है।

कृषि विभाग के दो फार्मों को लीज पर देने की मंजूरी

लखनऊ। कैबिनेट ने पीलीभीत एवं बाराबंकी में स्थित कृषि विभाग के प्रक्षेत्रों (फार्मों) को लीज पर दिए जाने के दो अलग-अलग प्रस्तावों को हरी झंडी प्रदान कर दी है। इसमें एक सहकारी क्षेत्र की संस्था है जबकि दूसरी केन्द्र सरकार की एजेन्सी है। पहला फार्म बाराबंकी जिले के मलिनपुर में है जिसकी 31 एकड़ भूमि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड को टिश्यू कल्चर लैब बनाने को दिया जाएगा।